

## एटा किशोर आत्महत्या प्रकरण: मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद चारों आरोपी पुलिसकर्मियों निलंबित

<https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/etah-suicide-case-news-four-accused-policemen-suspended-in-etah>

एटा के बापूनगर निवासी 15 साल के अभिषेक सिंह के आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी बनाए गए चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अभिषेक सिंह ने 21 सितंबर को घर पर ही तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में चार पुलिसकर्मियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट उसी दिन अभिषेक के पिता रवेन्द्र सिंह की तहरीर पर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई थी। अफसरों का कहना था कि प्राथमिक जांच के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

संबंधित खबर- एटा: पुलिस की कार्रवाई से आहत 15 साल के किशोर ने दी जान, मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट

इसके बाद मृतक के पिता ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की थी। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी से रिपोर्ट तलब की। बाद में रवेन्द्र सिंह ने विवेचना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। विवेचना की अदालत द्वारा मॉनीटरिंग किए जाने की उनकी मांग मान ली गई।

एसएसपी ने चारों पुलिसकर्मियों को किया निलंबित

सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदयवीर सिंह ने आरोपित चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। उस समय कोतवाली नगर में तैनात उपनिरीक्षक मोहित राना, उपनिरीक्षक शिवकुमार, हेड कांस्टेबल उपेंद्र कुमार और कांस्टेबल रवीश कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

रवेन्द्र का आरोप था कि इन चारों सिपाहियों ने 9 मार्च को पिज्जा लेने जा रहे उनके पुत्र अभिषेक को पकड़ लिया। 12 मार्च को मादक पदार्थ का फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। 25 जुलाई को जेल से छूटने के बाद अभिषेक तनाव में रहने लगा। जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली।

एसएसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि पूर्व में चारों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। विवेचना के क्रम में विभागीय कार्रवाई के तहत उनको निलंबित किया गया है। जिससे विवेचना की निष्पक्षता पर कोई प्रभाव न पड़ सके।

## **PM Modi To Address 28th NHRC Foundation Day Programme Today**

<https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-to-address-28th-nhrc-foundation-day-programme-tomorrow-2572193>

Prime Minister Narendra Modi will address the 28th National Human Rights Commission (NHRC) foundation day programme on Tuesday.

The Prime Minister said today that NHRC plays an important role in our nation in protecting the human rights and dignity of the marginalised.

"At 11 AM tomorrow, 12th October, will address the 28th NHRC Foundation Day programme. The NHRC plays an important role in our nation in protecting the human rights and dignity of the marginalised," tweeted PM Modi.

As per a Prime Minister's office release, NHRC was set up under the Protection of Human Rights Act 1993 on October 12, 1993 for the promotion and protection of human rights.

The Commission takes cognizance of any form of human rights violations, conducts enquiries and in cases of violation of human rights, recommends to the public authorities for payment of compensation to the victims, other remedial and legal measures against the erring public servants.

## **NHRC issues notices to Jammu and Kashmir Government, police over targeted killings of minorities**

<https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-notices-to-jammu-and-kashmir-government-police-over-targeted-killings-of-minorities/article36943057.ece>

The National Human Rights Commission has issued notices to the Jammu and Kashmir government and police over the recent spate of targeted killings of civilians from minority communities.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the DGP of the Union Territory on October 9 after taking suo motu cognisance of media reports the previous day. The officials were asked to respond within four weeks, according to the proceedings.

“The painful incidents of killing of civilians allegedly by the terrorists are a serious threat to the democratic fibre of the country and people’s right to life, liberty, equality and dignity. Targeted killings of those who are not Kashmiri Muslims is an attempt to keep non-Muslims out of the Valley. It is a gross violation of human rights of minority communities in the Valley, which must be stopped,” the NHRC observed.

The Commission referred to news reports about the killing of two government school teachers, Supinder Kaur, a Sikh, and Deepak Chand, a Hindu, in Srinagar on October 7. This was after well-known pharmacist Makhan Lal Bindroo, from the Kashmiri Pandit community, was gunned down on October 5 in Srinagar. On the same day, a Bihar-native, street food-seller Virender Paswan, was killed.

### **Suo motu cognisance**

“The Commission takes suo motu cognisance of the incident and directs issuance of notices to the Chief Secretary, Jammu & Kashmir and the DGP, Jammu & Kashmir calling for a detailed report in the matter including present status of the investigation being conducted and steps be taken or proposed to be taken by the authorities to safeguard innocent citizens’ lives from being killed in a targeted manner,” the NHRC said.

Two other civilians who were shot dead last week, Mohammad Shafi Lone and Majid Ahmad Gojri, were not mentioned in the NHRC proceedings.

दैनिक जागरण/ UNI

## **NHRC का 28वां स्थापना दिवस आज, 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल**

<https://www.jagran.com/news/national-pm-modi-to-address-28th-nhrc-foundation-day-programme-today-22105610.html>

<http://www.univarta.com/modi-to-address-28th-foundation-day-program-of-nhrc/india/news/2530820.html>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission, NHRC) के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में मानवाधिकार संरक्षण व NHRC की अहम भूमिका है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई।

At 11 AM tomorrow, 12th October, will address the 28th NHRC Foundation Day programme. The NHRC plays an important role in our nation in protecting the human rights and dignity of the marginalised.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा था, 'कल (मंगलवार) सुबह 11 बजे 28 वें NHRC फाउंडेशन डे कार्यक्रम को संबोधित करूंगा।' ट्वीट में उन्होंने आयोग की सराहना करते हुए उल्लेखनीय भूमिका का भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit Shah) और जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Kumar Mishra) भी शामिल होंगे। जस्टिस मिश्रा आयोग के चेयरपर्सन हैं।

मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 के तहत आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ की गई थी। NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेता है, जांच करता है और सार्वजनिक प्राधिकारों द्वारा पीड़ितों को दिए जाने के लिए मुआवजे की सिफारिश करता है।

यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच करता है और सार्वजनिक प्राधिकारों द्वारा पीड़ितों को दिए जाने के लिए मुआवजे की सिफारिश करता है। भारत में NHRC, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया के अन्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों

(NHRI) के साथ समन्वय करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसने संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्य मानवाधिकार निकायों के साथ-साथ नागरिक समाज के सदस्यों, वकीलों और कई देशों के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडलों की भी मेजबानी की है।

## NHRC Foundation Day: पीएम मोदी आज राष्ट्रीय

### मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम

<https://www.abplive.com/news/india/prime-minister-narendra-modi-to-address-28th-nhrc-foundation-day-programme-today-1981058>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे संबोधन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र में मानवाधिकार की रक्षा और वंचितों की गरिमा की रक्षा करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अहम भूमिका है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा- “कल सुबह ग्यारह बजे, 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एनएचआरसी हमारे देश में मानवाधिकारों और वंचितों की गरिमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।”

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। आयोग किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन का स्वतः संज्ञान लेता है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पड़ताल करता है, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये लोकाधिकारियों को अनुमोदन करता है, मानवाधिकारों का हनन करने वाले जनसेवकों के खिलाफ कानूनी और अन्य दण्डनीय कार्रवाई करता है।

# Killing of minorities a threat to democratic fabric of India: NHRC

## NHRC issues notices to the J&K Govt., police over attacks

**DAMINI NATH**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Jammu and Kashmir Government and the police over the recent spate of targeted killings of civilians from minority communities.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director-General of Police (DGP) of the Union Territory on October 9 after taking *suo motu* cognisance of media reports the previous day. The officials were asked to respond within four weeks, according to the proceedings. The painful incidents of killing of civilians al-

legedly by the terrorists are a serious threat to the democratic fabric of the country and people's right to life, liberty, equality and dignity, it observed. "Targeted killings of those who are not Kashmiri Muslims is an attempt to keep non-Muslims out of the Valley. It is a gross violation of human rights of minority communities in the Valley," it added.

The commission referred to news reports about the killing of two government school teachers, Supinder Kaur, a Sikh, and Deepak Chand, a Hindu, in Srinagar on October 7. This was after well-known pharmacist Makhan Lal Bindroo, from

the Kashmiri Pandit community, was gunned down on October 5 in Srinagar. On the same day, Virender Paswan, a street food vendor from Bihar, was killed.

"The commission takes *suo motu* cognisance of the incident and directs issuance of notices to the Chief Secretary, Jammu & Kashmir, and the DGP, Jammu & Kashmir, calling for a detailed report in the matter, including present status of the investigation being conducted and steps be taken or proposed to be taken by the authorities to safeguard innocent citizens' lives from being killed in a targeted manner," it said.



## **पीएम मोदी करेंगे एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस को संबोधित**

नई दिल्ली। मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का 28 वां स्थापना दिवस मंगलवार को आयोजित होगा। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस आयोजन को संबोधित करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण कानून के तहत एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ की गई थी। ब्यूरो

## ***NHRC issues notices on J&K killings***

NEW DELHI, Oct 11:

The National Human Rights Commission has issued notices to the Jammu and Kashmir Government and police over the recent spate of targeted killings of civilians from minority communities.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the DGP of the Union Territory on October 9 after taking suo motu cognisance of media reports the previous day. The officials were asked to respond within four weeks, according to the pro-

***(Contd on page 6 Col 7)***

## ***NHRC issues notices on J&K killings***

ceedings.

"The painful incidents of killing of civilians allegedly by the terrorists are a serious threat to the democratic fibre of the country and people's right to life, liberty, equality and dignity. Targeted killings of those who are not Kashmiri Muslims is an attempt to keep non-Muslims out of the Valley. It is a gross violation of human rights of minority communities in the Valley, which must be stopped," the NHRC observed.

The Commission referred to news reports about the killing of two Government school teachers, Supinder Kaur, a Sikh, and Deepak Chand, a Hindu, in Srinagar on October 7. This was after well-known pharmacist Makhan Lal Bindroo, from the Kashmiri Pandit community, was

gunned down on October 5 in Srinagar. On the same day, a Bihar-native, street food-seller Virender Paswan, was killed.

"The Commission takes suo motu cognisance of the incident and directs issuance of notices to the Chief Secretary, Jammu & Kashmir and the DGP, Jammu & Kashmir calling for a detailed report in the matter including present status of the investigation being conducted and steps be taken or proposed to be taken by the authorities to safeguard innocent citizens' lives from being killed in a targeted manner," the NHRC said.

Two other civilians who were shot dead last week, Mohammad Shafi Lone and Majid Ahmad Gojri, were not mentioned in the NHRC proceedings. (Agencies)



# NHRC notice to Warangal CP over man's 'suspicious' death

Srinath.Vudali@timesgroup.com

**Hyderabad:** The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report from the Warangal police commissioner after a man raised doubts over the death of his father, who was buried by his stepmother and villager elders reportedly using a JCB claiming he died due to Covid-19 in May 2021.

T Santosh Reddy, a businessman, said his father Sudhakar Reddy had passed away on May 23, 2021. He said he was not present when the death happened and for the final rites

"I have a strong suspicion that it could be a murder. So, I approached Velair police station and senior officials seeking their intervention. As Covid-19 was at the peak at that time, sub-inspector of police asked me to wait for some time on humanitarian grounds and assured justice," Santosh Reddy told **TOI**.

When contacted, Tarun Joshi clarified to **TOI** that in the written complaint lodged by Santosh Reddy at the local police station after the death of his father, he did not mention about suspicion or foul play

As police failed to help him exhume Sudhakar Reddy's body and conduct a post-mortem examination after three months and even giving a representation at the office of the director general of police, Santosh Reddy approached NHRC, which sought a report from Warangal police commissioner Tarun Joshi in four weeks.

When contacted, Tarun Joshi clarified to **TOI** that in the written complaint lodged by Santosh Reddy at the local police station after the death of Sudhakar Reddy, he did not mention about suspicion or foul play.

"The complainant then claimed that he was not informed about the death of his father by his stepmother and others. Accordingly, he sought action against them. So, with court's permission a case was then registered under Section 297 and other relevant sections of the IPC. In the case, a charge sheet was also filed against the accused," the CP said, adding that in view of NHRC seeking a report, a fresh inquiry would be done by police.

Santosh Reddy claimed a sub-inspector of police had suggested not to level the charge of foul play in the written complaint on humanitarian grounds since exhuming the body or others reasons would put several people at the risk of contracting Covid-19. "But he assured justice after some days. Later, we never got any response and I was not even given a copy of the FIR," the complainant claimed.

**पीएम आज मानवाधिकार****आयोग को संबोधित करेंगे**

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। पीएमओ ने बताया कि मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 के तहत आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ की गई थी। एनएचआरसी मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेता है, जांच करता है और सार्वजनिक प्राधिकारों द्वारा पीड़ितों को दिए जाने के लिए मुआवजे की सिफारिश करता है।

## **पीएम मोदी करेंगे एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस को संबोधित**

नई दिल्ली। मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का 28 वां स्थापना दिवस मंगलवार को आयोजित होगा। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस आयोजन को संबोधित करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण कानून के तहत एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ की गई थी। ब्यूरो



# Killing of minorities a threat to democratic fabric of India: NHRC

## Panel issues notices to the J&K Govt., police over attacks

**DAMINI NATH**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Jammu and Kashmir Government and the police over the recent spate of targeted killings of civilians from minority communities.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director-General of Police (DGP) of the Union Territory on October 9 after taking *suo motu* cognisance of media reports the previous day. The officials were asked to respond within four weeks, according to the proceedings. The painful incidents of killing of civilians al-

legedly by terrorists were a serious threat to the democratic fabric of the country and people's right to life, liberty, equality and dignity, it observed. "Targeted killings of those who are not Kashmiri Muslims is an attempt to keep non-Muslims out of the Valley. It is a gross violation of human rights of minority communities in the Valley," it added.

The commission referred to news reports about the killing of two government school teachers, Supinder Kaur, a Sikh, and Deepak Chand, a Hindu, in Srinagar on October 7. This was after well-known pharmacist Makhan Lal Bindroo, from

the Kashmiri Pandit community, was gunned down on October 5 in Srinagar. On the same day, Virender Paswan, a street food vendor from Bihar, was killed.

"The commission takes *suo motu* cognisance of the incident and directs issuance of notices to the Chief Secretary, Jammu & Kashmir, and the DGP, Jammu & Kashmir, calling for a detailed report in the matter, including present status of the investigation being conducted and steps be taken or proposed to be taken by the authorities to safeguard innocent citizens' lives from being killed in a targeted manner," it said.

# Killing of minorities a threat to democratic fabric of India: NHRC

## Panel issues notices to the J&K Govt., police over attacks

**DAMINI NATH**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Jammu and Kashmir Government and the police over the recent spate of targeted killings of civilians from minority communities.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director-General of Police (DGP) of the Union Territory on October 9 after taking *suo motu* cognisance of media reports the previous day. The officials were asked to respond within four weeks, according to the proceedings. The painful incidents of killing of civilians al-

legedly by terrorists were a serious threat to the democratic fabric of the country and people's right to life, liberty, equality and dignity, it observed. "Targeted killings of those who are not Kashmiri Muslims is an attempt to keep non-Muslims out of the Valley. It is a gross violation of human rights of minority communities in the Valley," it added.

The commission referred to news reports about the killing of two government school teachers, Supinder Kaur, a Sikh, and Deepak Chand, a Hindu, in Srinagar on October 7. This was after well-known pharmacist Makhan Lal Bindroo, from

the Kashmiri Pandit community, was gunned down on October 5 in Srinagar. On the same day, Virender Paswan, a street food vendor from Bihar, was killed.

"The commission takes *suo motu* cognisance of the incident and directs issuance of notices to the Chief Secretary, Jammu & Kashmir, and the DGP, Jammu & Kashmir, calling for a detailed report in the matter, including present status of the investigation being conducted and steps be taken or proposed to be taken by the authorities to safeguard innocent citizens' lives from being killed in a targeted manner," it said.